



भारत के वदियुत बाज़ार का केंद्रीकरण

प्रलिस के लयि:

यूरोपीय संघ, बाज़ार आधारति आर्थकि प्रेषण (MBED), वन नेशन वन ग्रडि वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003, वदियुत वतिरण कंपनयिँ (DISCOMs), नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ।

मेन्स के लयि:

बाज़ार आधारति आर्थकि प्रेषण (MBED) मॉडल, MBED के केंद्रीकृत मॉडल से संबंघ चतिारैँ ।

चर्चा में क्यौं?

भारत अपनी [वदियुत बाज़ार](#) प्रणाली को [वकिेंद्रीकृत](#), [स्वैच्छकि](#) और [अल्पकालकि](#) बाज़ार से एक अनविर्य पूल मॉडल में बदल रहा है जो नश्चिती मूल्य अनुबंधों को समाप्त करता है, जबकि [यूरोपीय संघ](#) इसके वपिरीत नीतयिँ अपना रहा है ।

वदियुत बाज़ार से संबंघति यूरोपीय संघ की नीति:

- यूरोपीय संघ अपने वदियुत बाज़ार में परिवर्तन कर रहा है क्यौंकि गैस की कमी के कारण वर्ष 2022 में वदियुत की कीमतें काफी बढ़ गई हैं ।
 - कीमतें उच्च इसलिये हुई क्यौंकि वदियुत की कीमतें सबसे महँगे वदियुत संयंत्र आमतौर पर गैस संयंत्र द्वारा नश्चिती की जाती हैं ।
- [यूरोपीय आयोग](#) वदियुत संयंत्रों द्वारा वदियुत बेचने के वभिन्न तरीकों पर वचिार कर रहा है ।
 - वे दीर्घकालकि अनुबंधों का उपयोग करना चाहते हैं जो वदियुत संयंत्रों को उनकी वदियुत के लयि एक नश्चिती मूल्य देते हैं ।
 - इससे घरों और व्यवसायों के लयि वदियुत की कीमतों को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी ।

भारत का नया बाज़ार-आधारति आर्थकि प्रेषण (MBED) मॉडल:

- भारत **MBED** तंत्र नामक एक नया वदियुत बाज़ार मॉडल वकिसति कर रहा है ।
 - यह देश की लगभग **1,400 बलियन यूनिट की वार्षकि वदियुत खपत को प्रेषण के लयि केंद्रीकृत करेगा** ।
- MBED केंद्र के ['वन नेशन, वन ग्रडि, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस'](#) फॉर्मूले के अनुरूप वदियुत बाज़ारों को बढ़ावा देने का एक तरीका है ।
 - यह सुनश्चिती करेगा कपूरे तंत्र की मांग को पूरा करने के लयि देश भर में सबसे सस्ते वदियुत उत्पादन संसाधनों की आपूर्तिकी जाए और इसलिये यह वतिरण कंपनयिँ एवं जनरेटर दोनों के लयि फायदेमंद होगा । साथ ही इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को बचत भी होगी ।
 - यह वकिेंद्रीकृत मॉडल स्पष्ट बदलाव को भी चहिनति करेगा जो [वदियुत अधनियम, 2003](#) द्वारा समर्थति है ।
- वर्तमान में वदियुत ग्रडि को [राज्य लोड डिसिपैच सेंटर \(SLDC\)](#) द्वारा प्रबंधति राज्य-वार स्वायत्त नयितरण क्षेत्रों में बाँटा गया है जनिका पर्यवेक्षण [क्षेत्रीय लोड डिसिपैच सेंटर \(RLDC\)](#) और [नेशनल लोड डिसिपैच सेंटर \(NLDC\)](#) द्वारा कयिा जाता है ।
 - MBED मॉडल राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य दोनों में वदियुत प्रेषण का एक केंद्रीकृत समय-नश्चिती प्रस्तावति करता है । यह नया मॉडल मौजूदा वकिलपों और डिसिपैच को सीमति कर देगा तथा [स्टेट लोड डिसिपैच सेंटर](#) को वास्तवकि समय में बजिली खरीदनी या बेचनी होगी, भले ही यह मांग को संतुलति करने के लयि ही क्यौं न हो ।
- **GNA (जनरल नेटवरक एक्सेस)**, जो अधिक खुला और अनुकूलनीय है, को भारत में ऊर्जा ग्रडि के लयि दशिा-नश्चिती के एक नए सेट के रूप में भी वकिसति कयिा जा रहा है ।

MBED के केंद्रीकृत मॉडल से जुड़ी चतिारैँ:

- **राज्य की स्वायत्तता पर प्रभाव:** MBED का राज्यों के वदियुत क्षेत्र के प्रबंधन में सापेक्ष स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें उनके स्वयं के उत्पादन केंद्र भी शामिल हैं और यह राज्य के स्वामित्व वाली ज़्यादातर **बजिली वतिरण कंपनियों (डसिक्ॉम)** को पूरी तरह से केंद्रीकृत तंत्र पर निर्भर कर देगा।
- **उभरते हुए वकिंद्रीकृत बाज़ार के साथ टकराव:** यह नए बाज़ार के विकास में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जैसे कुल ऊर्जा उत्पादन में **नवीकरणीय ऊर्जा** का वसितार और पॉवर ग्रिड से जुड़ने वाले **इलेक्ट्रिक वाहनों** की संख्या में वृद्धि आदि।
 - प्रभावी ग्रिड प्रशासन और संचालन के लिये वास्तव में बाज़ारों और स्वैच्छकियों पूलों के व्यापक वकिंद्रीकरण की आवश्यकता है।
- **गरे क्षेत्र:** कुछ वदियुत संयंत्र, जैसे मुंबई में ट्रांसमिशन **TPS** और **NCR** क्षेत्र में दादरी **TPS** को बंद करने के लिये मजबूर किया जाएगा।
 - ये पावर स्टेशन मुंबई या दल्लि जैसे प्रमुख शहरों में सुरक्षा और ग्रिड फेल होने की स्थिति में संचालन के लिये महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह

- वदियुत भारतीय संवधान की समवर्ती सूची का वषिय है, अतः नए मॉडल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्यों की सफारिशों पर वचिार किया जाना चाहिये।
- **सकियोरटी कांस्ट्रेंड इकोनॉमिक डसिपैच (SCED)**, NLDC द्वारा वकिसति एक एल्गोरथिम संभावति समाधान हो सकता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी आधार पर निर्धारति निर्णयों पर सूचति करने में नयामकों की सहायता करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नयामक बोर्ड (PNGRB) भारत सरकार द्वारा स्थापति पहला नयामक नकिय है।
2. PNGRB के कार्यों में से एक गैस के लिये प्रतसिपर्द्धी बाज़ार सुनश्चिति करना है।
3. PNGRB के वदियुत फैसलों के खलिफ अपील अपीलीय न्यायाधकिरण के समक्ष की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा सरकार की एक योजना 'उदय'(UDAY) का उद्देश्य है? (2016)

- (a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी और वतितीय सहायता प्रदान करना।
- (b) वरष 2018 तक देश के हर घर में वदियुत पहुँचाना।
- (c) कोयला आधारति वदियुत संयंत्रों को समय के साथ प्राकृतिक गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय वदियुत संयंत्रों से बदलना।
- (d) वदियुत वतिरण कंपनियों के बदलाव और पुनरुद्धार के लिये वतित प्रदान करना।

उत्तर: (d)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

